THE RIGHT TO INFORMATION ACT

1. Who can obtain information under RTI Act?

Ans. Any citizen of India can obtain information under the RTI Act.

2. From whom the information can be obtained?

Ans. Information can be obtained from any public authority.

3. Which information cannot be asked under RTI Act?

Ans. (1) Under this Act there is no obligation to give the following information:-

a) information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the state, relation with foreign state or lead to incitement of an offence;

b) information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court;

c) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;

d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information;

e) information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information;

f) information received in confidence from foreign government;

g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;

h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers.

सूचना का अधिकार

प्रश्न सूचना के अधिकार नियम के अन्तर्गत कौन सूचना प्राप्त कर सकता है?

उतर इस नियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है सूचना प्राप्त कर सकता हैं।

प्रश्न सूचना किससे प्राप्त की जा सकती है?

उतर सूचना किसी भी सरकारी अधिकारी से मांगी जा सकती है।

प्रश्न कौन सी सूचना, सूचना के अधिकार नियम के अन्तर्गत नहीं मांगी जा सकती?

उतर 1) इस नियम के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना देने को बाध्य नहीं है

क) जिस सूचना को देने से भारत की प्रभुता, पवित्रता, सुरक्षा, युद्व की कूटनीति या वैज्ञानिक या राज्य के आर्थिक हितों या विदेशी राज्यों के सम्बन्ध या किसी अपराध के बढावा देने बारे, की सूचना देने से विपरीत प्रभाव पड़े।

ख) ऐसी सूचना जिसको किसी अदालत या ट्रिबूनल ने छापने पर प्रतिंबध लगाया हो या जिसको बताने से अदालत की अवमानना होती हो।

ग) जिस सूचना को देने से लोकसभा या राज्य विद्यानसभा के विशेष अधिकारों का हनन होता हो।

घ) व्यापारिक विश्वास, व्यापार की गुप्तता या किसी की मानसिक बुद्वि सम्बंधिंत सूचना देने से किसी तीसरे व्यक्ति की स्पर्धा करने की स्थिति का नुकसान हो अथवा जब तक कि सक्षम अधिकारी को यह विश्वास न हो कि सूचना देना सार्वजनिक हित में ना हो।

ङ) किसी व्यक्ति के पास जो न्याय से सम्बधिंत अधिकारों के कारण सूचना जो उसके पास हो, जब तक सक्षम अधिकारी को यह ना लगे कि सूचना देना सार्वजनिक हित में हो।

च) ऐसी सूचना जो किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हो।

छ) ऐसी सूचना जिसको देने से किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो या उसकी शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो या किसी को सुरक्षा प्रदान करने की सहायता में बाधक हो।

ज) ऐसी सूचना जो किसी जांच की प्रक्रिया या अभियोग में रूकावट की संभावना पैदा करे।

झ) मंत्री परिषद के दस्तावेज मय मंत्रियों, सचिवों व अन्य अधिकारियों की सभा के विचारों का रिकार्ड।

Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over:

Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed;

r) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure.

Provided that the information, which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature, shall not be denied to any person.

(2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.

(3) Subject to the provisions of clauses (a), (c) and (i) of sub-section (1), any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section;

Provided that where any question arises as to the date from which the said period of twenty years has to be computed, the decision of the Central Government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this Act.

(4) Without prejudice to the above provisions, a Central Public information Officer or State Public Information Officer, as the case may be may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State.

पुर्वनिर्दिष्ट किया जाता है कि मन्त्री मण्डल द्वारा निर्णय लेने के बाद तथा मामले के पूर्ण या पूरा होने पर उन निर्णयों को इनके कारण सहित तथा दस्तावेज जिसके आधार पर वह निर्णय लिए गए, को सार्वजनिक किया जाएगाः

यह भी पुनः पुर्वनिर्दिष्ट किया जाता है कि जो मामले इस धारा के अर्न्तगत दी गई छूट के अर्न्तगत आते है उन्हे गुप्त रखा जाऐगा।

ञ) सूचना जो कि व्यक्तिगत सूचना से सम्बधित है, जिसका भेद प्रकाशन का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई सम्बंध नही है, अथवा किसी व्यक्ति की निजता पर अनाधिकृत उल्लंघन हो सिवाय कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी अथवा राज्य जन सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकार, जैसी भी स्थिति हो, संतुष्ट हो कि व्यापक जनहित में ऐसा भेद प्रकाशन न्यायसगंत है।

पुर्वनिर्दिष्ट किया जाता है कि सूचना, जो कि संसद या राज्य विधानसभा को प्रदान करने से मना नही किया जा सकता वो किसी भी व्यक्ति को देने से मना नही किया जाएगा।

2) राजकीय गोपनीय अधिनियम 1923 (1923 का 19) में वर्णित किसी भी प्रावधान के होते हुए भी अथवा उपधारा (1) के अनुसार किसी भी अधिकृत छूट के होते हुए भी एक जन प्राधिकरण, सूचना पर पहुंच की स्वीकृति दे सकती है, यदि भेद प्रकाशन से संरक्षित हितों के नुकसान की तुलना में जनहित को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है।

3) उपधारा (1) के अनुच्छेद (ए), (सी) और (आई) में वर्णित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई वाका अगर धारा 6 के अर्न्तगत किए गए अनुरोध की तिथि से 20 वर्ष पहले घटित हुआ हो तो ऐसे घटना, कार्यक्रम, विषय से संबंधित जानकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

पुर्वनिर्दिष्ट किया जाता है कि जहां ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि उपरोक्त 20 वर्ष की अवधि की गणना किसी तिथि से की जाऐगी, केन्द्रीय सरकार का निर्णय, इस अधिनियम के अर्न्तगत सामान्य अपील के प्रावधानों के अधीन अन्तिम होगा।

4) उपरोक्त प्रावधानों के प्रभावित किए बगैर, एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सूचना के अनुरोध को निरस्त कर सकता है जहां सूचना देने के ऐसे अनुरोध से, राज्य के अतिरिक्त किसी व्यक्ति से निहित प्रकाशन अधिकार का उल्लंघन सम्मिलित होता है।

4. What is the prescribed fee?

Ans. Rule 5 of the Haryana Right to Information Rules, 2009 provides as under:-

5. (1) An application for obtaining any information under sub-section (1) of the section 6 shall be accompanied with a fee of Rs.50/-

(2) For providing information under sub-section (1) of section 7, the fee shall be charged from the applicant at the following rates, namely:-

(a) Rs.2/- for each page in A-4 or A-3 size paper, created or copies; and

(b) if information is to be provided on a large size of paper than that specified in-clause (a), the actual cost shall be charged.

(3) For providing information under sub-section (5) of section 7, the fee shall be charged from the applicant at the following rates, namely:-

(a) Rs.50/- for providing information in a floppy;

(b) Rs.100/- for providing information in diskette; and

(c) if information sought is of such a nature, which is contained in a printed document, of which a price has been fixed, then that information shall be provided after charging the price, fixed for that printed document. However, if only an extract or page of such a printed document is asked for, then a fee of Rs.2/- per page shall be charged.

(4) No fee for inspection of record shall be charged, if such an inspection is made for one hour only. However, if inspection is made for a period of more than one hour, then a fee of rupees ten shall be charged for every fifteen minutes in excess of first hour. Every fraction of the period above fifteen minutes shall be construed as a complete period of fifteen minutes and it shall be charged as full period of fifteen minutes.

5. In how much time the information has to be supplied?

Ans. The Public Information Officer or the Assistant Public Information Officer, as the case may be, has to supply information within 30 days of the receipt of the request, or has to reject the request for any of the reasons specified in the Act, within that period.

प्रश्न निर्धारित शुल्क क्या है?

उत्तर हरियाणा सूचना अधिकार नियम 2009 के नियम 5 के अनुसारः–

5 (1) धारा 6 उपधारा (1) के तहत सूचना लेने के लिए दी गई अर्जी के साथ पचास रूपये शुल्क लगेगा।

(2) धारा 7 उपधारा (1) के तहत सूचना प्रदान करने के लिये, आवेदनकर्ता से निम्नलिखित शुल्क लिया जायेगाः–

(अ) A-3 और A-4 साईज के कागज पर पहली और नकल कापी के लिए दो रूपये प्रति पृष्ठ; और

(ब) अगर सूचना (अ) के अतिरिक्त बड़े कागज पर देनी हो तो वास्तविक खर्च लिया जायेगा।

(3) धारा 7 उपधारा (5) के तहत सूचना देने के लिये, आवेदनकर्ता से निम्नलिखित दर पर शुल्क लिया जायेगाः–

(क) 'फॅलापी' से सूचना देने के लिये Rs.50/-

(ख) 'डिस्क' से सूचना देने के लिये Rs.100/-

(ग) अगर मांगी हुई सूचना छपे हुये दस्तावेज, जिसका मुल्य निश्चित है, के रूप में है, तो वह सूचना निश्चित मुल्य, लेकर ही दी जायेगी, परन्तु अगर छपे हुऐ दस्तावेज का अंश या पृष्ठ ही मांगा गया हो, तो शुल्क Rs.2/- प्रति पृष्ठ ली जायेगी।

(4) रिकार्ड की जांच के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, अगर जांच एक घण्टे के लिये की जाती है। परन्तु, अगर जांच एक घण्टे से ज्यादा समय के लिये की जाती है तो पहले घण्टे के अतिरिक्त हर 15 मिनट के लिये 2-10/- का शुल्क लिया जायेगा। 15 मिनट से उपर हुये हर अंश को पूरे 15 मिन्ट ही माना जायेगा और उस पर पुरे 15 मिन्ट का शुल्क लिया जायेगा।

प्रश्न सूचना कितने समय में प्रदान की जायेगी?

उत्तर जन सूचना अधिकारी या सहायक जन सूचना अधिकारी या जिसके पास भी सूचना देने का अध्किार होगा वह सूचना आवेदन प्राप्त करने के बाद 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान करेगा या कारण सहित आवेदन को रद्द करेगा।

6. First Appeal lies to which Authority and what is the period of limitation for filing the first appeal?

Ans. The Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has to dispose off the request for information within a period of 30 days as stated above. Where the applicant does not receive a decision within said specified time or is aggrieved by a decision of the Public Information Officer, then he may within 30 days from the expiry of such period or from the receipt of such decision, prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be.

7. Second appeal lies to which Authority and what is the period within which the second appeal is to be filed?

Ans. Second appeal against the aforesaid decision shall lie within 90 days from the date on which decisions should have been made or was actually received. The second appeal is to be filed before the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be.

8. What are the offences and punishments under RTI Act?

Ans. Where the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has without any reasonable cause, refused to receive any application for information or has not furnished information within the specified time, or has malafidely denied the request for information, or has knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or has destroyed information which was the subject of the request or has obstructed in any manner in furnishing the information, the Central information commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal, shall impose a penalty of Rs.250/- each day, till application is received or information is furnished. However, total amount of such penalty should not exceed Rs.25,000/-.

प्रश्न किस प्राधिकरण पहली अपील पड़ती है और पहली अपील डालने के लिए समय सीमा क्या है?

उत्तर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी या जो भी सूचना देने का अधिकार रखता हो, वह सूचना, आवेदक को तीस दिन में निर्धरित करेगा जहां पर भी आवेदक वह सूचना निर्धारित उपरोक्त समय में प्राप्त नही करता या जो सूचना मिली है उससे सहमत नही होता, तो आवेदक ऐसी अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर सूचना या मिलने के 30 दिन भीतर, उसकी अपील उस अधिकारी के पास करेगा जो केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी या राज्य जनसूचना अधिकारी से वरिष्ठ होगा।

प्रश्न दूसरा अपील प्राधिकारी कौन है और दूसरी अपील दायर करने के लिए समय सीमा क्या है?

उत्तर उपरोक्त निर्णय के खिलाफ अपील 90 दिन के भीतर की जानी चाहिए जिस दिन तक निर्णय दिया जाना चाहिए था या जिस दिन निर्णय प्राप्त हुआ। द्वितीय अपील केन्द्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग, या जो भी अधिकार रखता है, के पास दायर की जाती है।

प्रश्न जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपराध क्या है और उनके के लिए दण्ड क्या है?

उत्तर जहां पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी या जो भी अधिकार रखता है, सूचना के लिए आवेदन को बिना उचित कारण लेने से इन्कार करता है, या वह निर्धरित समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान नही करता है, या गलत भावना के कारण सूचना देने से इन्कार करता है, या जानबुझ कर गलत जानकारी, या अधूरी, या भ्रामक जानकारी देता है, या मांगी गई सूचना को नष्ट करता है, या जानकारी देने में किसी भी प्रकार का अवरोधक बनता है, तब केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग या जो भी अधिकार रखता है शिकायत निर्धारण के समय या अपील निर्धारण के समय, प्रति दिन के लिए दोषी को 250/- प्रति दिन के हिसाब से दण्ड शुल्क लगा सकता है जब से आवेदन प्राप्त हुआ और या जब से जानकारी प्रदान की गई। कुल दण्ड शुल्क 25,000/- रूपये से अधिक नहीं होगा।

MGNREGA

1. What guarantee regarding employment is provided under this Act?

Ans. This Act provides not less than 100 days of guaranteed wage employment in a financial year, to every household in the rural areas, whose adult members, by application volunteer to do unskilled manual work.

2. What is the procedure for registration and obtaining job cards?

Ans. An application for purposes of registration under rural areas employment guarantee scheme has to be filed before the Sarpanch of the concerned village. A job card is issued to the registered family within 15 days. Photographs of the adult members of the family who are willing to work under this scheme has to be affixed on the card. The card remains valid for 5 years.

3. What is the procedure for obtaining employment?

Ans. For obtaining employment an application is to be filed before the Sarpanch of the concerned village where the person is registered.

4. What is the provision for compensation where the applicant is not provided with employment within 15 days of receipt of application?

Ans. In case the applicant is not provided with employment within 15 days of receipt of application, he shall be entitled to a Daily Unemployment Allowance at such rates as may specified by the State Government by notification in consultation with the State council. No such rate shall be less than one-fourth of the minimum wage rate for the first 30 days during the financial year and not less than one half of the minimum wage rate for the remaining period of the financial year. The liability of the State Government to pay unemployment allowance shall cease where the adult members of the household have received the total of at least 100 days of work within the financial year or where the household of the applicant has earned as much from the wages and unemployment allowance taken together which is equal to the wages for 100 days of working during the financial year.

5. Whether the applicant has to be provided with employment in his own village?

Ans. Yes the applicant is provided employment in his own village or in nearby village.